# Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

**3 नवंबर 2026 • हिंदी**

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 13 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

## 1 भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट के पास अपहृत मछली पकड़ने वाले जहाज 'अजिनी' को सशस्त्र समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया; चालक दल के सभी 20 सदस्य सुरक्षित

*Indian Navy frees hijacked fishing vessel 'Azini' from armed pirates off Somalia; all 20 crew members safe*

**SSC • Railway • Defence • General**

रक्षा मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को बताया कि भारतीय नौसेना ने 48 घंटे से अधिक समय तक चले त्वरित और सुव्यवस्थित अभियान में सोमालिया के तट के पास मछली पकड़ने वाले जहाज अजिनी (Azini) को सशस्त्र समुद्री लुटेरों के कब्जे से मुक्त कराया; चालक दल के सभी 20 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया और कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। अजिनी के पिछले महीने सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास सशस्त्र समुद्री लुटेरों के एक समूह द्वारा अपहरण किए जाने की सूचना मिली थी; मंत्रालय के अनुसार यह अपहरण समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा था, क्योंकि इस जहाज का इस्तेमाल क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर समुद्री लुटेरों के और हमलों के लिए 'मदर शिप' (मुख्य जहाज) के रूप में किया जा सकता था। नौसेना ने मिशन पर तैनात एक युद्धपोत को कार्रवाई के लिए भेजा, जिसे एक समुद्री निगरानी विमान का सहयोग मिला; लगातार निगरानी के बाद जहाज का पता लगाया गया, उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई और उसकी गतिविधि को सीमित करने तथा उसे भागने से रोकने के लिए सुनियोजित गैर-घातक उपाय अपनाए गए। भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान द्वारा सटीक एयरड्रॉप के माध्यम से मरीन कमांडो की अतिरिक्त तैनाती की गई, जिसके बाद नौसेना ने जहाज को अपने नियंत्रण में लिया, समुद्री लुटेरों के खतरे को निष्प्रभावी किया और चालक दल के सभी 20 सदस्यों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की। मंत्रालय के अनुसार यह अभियान नौसेना की उच्च परिचालन तत्परता और सेनाओं के बीच निर्बाध समन्वय के माध्यम से जटिल समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने की क्षमता को दर्शाता है, और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (फर्स्ट रिस्पॉन्डर) और पसंदीदा सुरक्षा भागीदार बने रहने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331872

## 2 भारत-अमेरिका त्रि-सेवा एचएडीआर अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ के 5वें संस्करण का विशाखापत्तनम में उद्घाटन; पहली बार एनडीआरएफ का दल भी भाग लेगा

*5th edition of India-US tri-service HADR exercise Tiger Triumph opens at Visakhapatnam; an NDRF team to take part for the first time*

**SSC • Railway • Defence • General**

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास के 5वें संस्करण 'टाइगर ट्रायम्फ 2026' का उद्घाटन समारोह 2 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम स्थित मैरीटाइम वारफेयर सेंटर (एमडब्ल्यूसी) में आयोजित किया गया। इस वर्ष यह अभ्यास 'टेबलटॉप एक्सरसाइज' (टीटीएक्स) के रूप में आयोजित किया जा रहा है; इसका उद्देश्य व्यापक स्तर पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के दौरान दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच समन्वय, संयुक्त रूप से योजना बनाने और अंतर-संचालनीयता को बेहतर बनाना है, और इस संस्करण का उद्देश्य संयुक्त बहु-क्षेत्रीय अभियानों (Combined Joint All-Domain Operations) के संचालन को सुगम बनाना भी है। समारोह की अध्यक्षता पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल विशाल बिश्नोई और अमेरिकी प्रशांत बेड़े के वाइस कमांडर रियर एडमिरल जोकिन जे. मार्टिनेज डी पिनिलोस ने की। भारतीय पक्ष की ओर से भारतीय नौसेना के समुद्री अभियानों के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ, भारतीय थल सेना के जमीनी बल, भारतीय वायु सेना की विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधि तथा तीनों सेनाओं के विशेष बलों के कर्मी इसमें शामिल हैं, और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का एक दल भी पहली बार इसमें भाग लेगा। अमेरिकी संयुक्त बल में अमेरिकी वायु सेना, थल सेना, मरीन कोर और नौसेना के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों के साथ-साथ अंतरिक्ष, साइबर, चिकित्सा और बम निरोधक (एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल) विशेषज्ञ भी शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास भारत और अमेरिका के रणनीतिक समुद्री हितों में बढ़ती निकटता और दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी को दर्शाता है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331900

## 3 आदित्य-एल1 के वीईएलसी से पता चला कि एक सौर विस्फोट सरल सममित बुलबुले की तरह नहीं, बल्कि असममित रूप से फैला: आईआईए का अध्ययन

*Aditya-L1's VELC shows a solar eruption expanded asymmetrically, not like a simple symmetric bubble: IIA study*

**SSC • Railway • Science • General**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के स्वायत्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आईआईए) के वैज्ञानिकों ने आदित्य-एल1 पर लगे विज़िबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (वीईएलसी) के डेटा से दिखाया है कि एक सौर विस्फोट, यानी कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई), सूर्य से बाहर की ओर एक सरल सममित बुलबुले की तरह नहीं फैला, जैसा पहले सोचा जाता था, बल्कि उसका फैलाव असमान रहा और उसका आकार असममित (विषम) हो गया; रिलीज़ के अनुसार एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित इस अध्ययन से यह बात पहली बार सामने आई। वैज्ञानिकों ने वीईएलसी के डेटा को नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी (एसडीओ) के पूरक अवलोकनों और त्रि-आयामी मॉडलिंग के साथ मिलाकर विस्फोट की पूरी 3-डी ज्यामिति और गतिकी का पुनर्निर्माण किया, और 5 अगस्त 2024 के उस सीएमई का अवलोकन किया जो सूर्य के पश्चिमी किनारे के पास एक सक्रिय क्षेत्र से निकला था। आदित्य-एल1 के 7 पेलोड में से प्राथमिक पेलोड वीईएलसी एक आंतरिक रूप से आच्छादित (इंटरनली ऑकल्टेड) कोरोनाग्राफ है, जो कोरोना में अत्यधिक आयनित लौह परमाणुओं से उत्पन्न 530.3 एनएम तरंगदैर्ध्य की हरी उत्सर्जन रेखा में स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए नए सीएमई का अध्ययन करता है; यह रेखा लगभग 1.8 मिलियन केल्विन तापमान वाले गर्म कोरोनल प्लाज़्मा को दर्ज करती है। इसके डेटा में ब्लू-शिफ्टेड और रेड-शिफ्टेड उत्सर्जन दिखा, जो प्रेक्षक की ओर आते और उससे दूर जाते प्लाज़्मा से उत्पन्न होता है। सममित फैलाव वाला मॉडल इस पैटर्न को दोबारा नहीं बना सका, जबकि झुके हुए सीएमई अक्ष और असममित पार्श्व फैलाव वाले मॉडल ने बना लिया। शोधकर्ताओं के अनुसार फैलाव में ऐसे अंतर सीएमई की गति और पृथ्वी पर उसके पहुंचने के समय पर असर डाल सकते हैं, जो अंतरिक्ष मौसम (स्पेस वेदर) के लिए अहम है। भारत की पहली अंतरिक्ष-आधारित सौर वेधशाला आदित्य-एल1 सितंबर 2023 में लॉन्च हुई थी और अब सूर्य-पृथ्वी एल1 बिंदु पर कार्यरत है; वीईएलसी को आईआईए ने होसाकोटे में क्रेस्ट (CREST) परिसर स्थित अपनी एमजीके मेनन लैब फॉर स्पेस साइंसेज में इसरो के उल्लेखनीय सहयोग से डिज़ाइन और निर्मित किया।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331935

## 4 स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा: आईसीडी, एक एसईजैड और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अधिकृत आयात गेटवे बनाने का प्रस्ताव

*Health Ministry proposes amending Rule 43A of the Drugs Rules, 1945 to add ICDs, an SEZ and Noida International Airport as authorised import gateways*

**SSC • Railway • General**

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को बताया कि उसने देश में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात के लिए अधिकृत प्रवेश स्थलों के नेटवर्क का विस्तार करने हेतु 'ड्रग्स रूल्स, 1945' के नियम 43ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नियम 43ए में उन अधिकृत बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क मार्गों और अन्य प्रवेश द्वारों को निर्धारित किया गया है, जिनके माध्यम से भारत में दवाओं का आयात किया जा सकता है। प्रस्तावित नए स्थानों में हरियाणा में सोनीपत, पियाला और हरसारू, उत्तर प्रदेश में दादरी, गुजरात में गांधीधाम/मुंद्रा, हैदराबाद (तेलंगाना) में सनत नगर और थिम्मापुर तथा बेंगलुरु (कर्नाटक) में व्हाइटफील्ड के इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी); कर्नाटक में बोम्मासांद्रा का विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड); और हवाई मार्ग से दवाओं के आयात के लिए उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार इन्हें आयात के लिए पहले से मौजूद अधिकृत नेटवर्क में जोड़ा जाएगा, जिसमें इंदौर (मध्य प्रदेश) के धननाद और तिही के आईसीडी तथा दवाओं के आयात के लिए पहले से अधिसूचित हवाई अड्डे शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार इस प्रस्ताव से आयातक अपने विनिर्माण केंद्रों, गोदामों और वितरण केंद्रों के करीब ही अपनी खेप की निकासी करा सकेंगे, जिससे देश के भीतर परिवहन की दूरी, लॉजिस्टिक्स लागत और देरी कम होगी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित संशोधन वाली ड्राफ्ट अधिसूचना आधिकारिक गजट में उपलब्ध है, और इस पर आपत्तियां और सुझाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव (दवा नियमन), कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली को या ईमेल से भेजे जा सकते हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331879

## 5 ट्राई ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए: एलएसए स्तर और आईपी-आधारित इंटरकनेक्शन की ओर बदलाव, 1 जनवरी 2027 से लागू

*TRAI releases Telecommunication Interconnection (Third Amendment) Regulations, 2026: shift to LSA-level and IP-based interconnection, effective 1 January 2027*

**SSC • Banking • General**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 3 नवंबर 2026 को "दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026" जारी किए, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। दूरसंचार में इंटरकनेक्शन का तात्पर्य उन तकनीकी, परिचालन और व्यावसायिक व्यवस्थाओं से है जो दो या दो से अधिक दूरसंचार नेटवर्कों को आपस में जोड़ती हैं, जिससे उनके बीच ट्रैफिक का प्रवाह संभव होता है और अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के उपयोगकर्ता एक-दूसरे से निर्बाध रूप से संवाद कर पाते हैं; ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ब) ट्राई को सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देती है। ट्राई ने अप्रैल 2025 में "इंटरकनेक्शन मामलों पर मौजूदा ट्राई विनियमों की समीक्षा" विषय पर प्रारंभिक-परामर्श पत्र जारी करके यह समीक्षा शुरू की और नवंबर 2025 में परामर्श पत्र जारी किया, जिस पर सत्रह हितधारकों ने टिप्पणियां और नौ हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियां दीं; जनवरी 2026 में एक खुली चर्चा (ओपन हाउस डिस्कशन) आयोजित की गई। यह संशोधन इंटरकनेक्शन देने वालों और लेने वालों को दूरसंचार ट्रैफिक के आदान-प्रदान के स्थानों पर आपसी सहमति बनाने की सुविधा देता है और मौजूदा लॉन्ग डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (एलडीसीए) और शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (एसडीसीए) स्तर के इंटरकनेक्शन से लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (एलएसए) स्तर के इंटरकनेक्शन की ओर बदलाव को आसान बनाता है; ट्राई के अनुसार ट्रैफिक को एलएसए-स्तर के इंटरकनेक्शन बिंदुओं (पीओआई) पर ले जाने से रूटिंग सरल होगी, सीमित नंबरिंग संसाधनों का प्रबंधन अधिक कुशलता से हो सकेगा, विलंब (लेटेंसी) कम होगा और सेवाओं की विश्वसनीयता बेहतर होगी। एलडीसीए/एसडीसीए-स्तर के पीओआई पर मौजूदा ट्रैफिक को तीन वर्षों के भीतर चरणबद्ध तरीके से एलएसए-स्तर के पीओआई पर ले जाया जाएगा। विनियमों के लागू होने के बाद स्थापित सभी नए इंटरकनेक्शन आईपी-आधारित होंगे, और ई1/टीडीएम-आधारित इंटरकनेक्शन पर काम कर रहे सभी मौजूदा पीओआई को तीन वर्षों के भीतर चरणबद्ध तरीके से आईपी-आधारित इंटरकनेक्शन में बदला जाएगा। अन्य बदलावों में सेवा प्रदाता द्वारा अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए स्वेच्छा से पीओआई सरेंडर करने का ढांचा (पहले विनियमों में केवल पीओआई के डिस्कनेक्शन का प्रावधान था); पुनर्मूल्यांकन पर दी जाने वाली बैंक गारंटी की वैधता और ऐसे पुनर्मूल्यांकन के अंतराल को छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने करना; इंटरकनेक्शन शुल्क या इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क के भुगतान में देरी पर सेवा प्रदाताओं की आपसी सहमति से तय ब्याज, जिसकी अधिकतम सीमा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक वर्ष की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में दो प्रतिशत जोड़कर बनने वाली दर होगी; एलएसए-स्तर के पीओआई पर ट्रैफिक के स्थानांतरण और आईपी-आधारित इंटरकनेक्शन की ओर माइग्रेशन की निगरानी के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं; तथा विनियमों के उल्लंघन पर वित्तीय दंड (फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव) का श्रेणीबद्ध ढांचा शामिल हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331941

## 6 प्रधानमंत्री ने लगभग 21,800 करोड़ रुपये की पुणे मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया; हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर कॉरिडोर शुरू

*PM Modi inaugurates and lays foundation stone of Pune Metro projects worth around ₹21,800 crore; Hinjawadi–Shivajinagar corridor opened*

**SSC • Railway • General**

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 नवंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 21,800 करोड़ रुपये की पुणे मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दस वर्ष पहले पुणे मेट्रो के पहले चरण का शिलान्यास करने को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हिंजेवाड़ी से शिवाजीनगर कॉरिडोर के उद्घाटन से एक बड़े आईटी हब को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि उसी दिन जिस नई लाइन पर काम शुरू हुआ, वह शहर के पुराने और नए इलाकों को और जोड़ेगी। उन्होंने बताया कि नए उद्घाटित कॉरिडोर का निर्माण सरकार और निजी क्षेत्र के साझा प्रयासों से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश का मेट्रो नेटवर्क 26 शहरों में लगभग 1,200 किलोमीटर तक फैल गया है, जिसमें प्रतिदिन एक करोड़ से अधिक लोग यात्रा करते हैं, और भारतीय मेट्रो नेटवर्क की गिनती दुनिया के शीर्ष तीन मेट्रो नेटवर्क में होती है। उन्होंने कहा कि 2014 में महाराष्ट्र में केवल 10 से 11 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू थीं, जबकि अब लगभग 175 किलोमीटर लाइनें सेवा में हैं और 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 680 किलोमीटर से अधिक लाइनों पर काम चल रहा है। उन्होंने फरवरी 2026 में अर्बन चैलेंज फंड को दी गई स्वीकृति का उल्लेख किया, जिसके लिए केंद्र सरकार एक लाख करोड़ रुपये की सहायता दे रही है और जिसका लक्ष्य शहरों में लाखों करोड़ रुपये का निवेश जुटाना है, और स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्र के साझेदारों से मिशन मोड में इस प्रयास से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कठिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में दुनिया की सबसे तेज़ विकास दर बनाए रखी है और विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 10 से 12 वर्षों के भीतर भारत में 50 करोड़ नागरिक अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332011

## 7 अंताल्या में होने वाले यूएनएफसीसीसी सीओपी31 में भारत समाधान-उन्मुख और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव

*India to pursue solution-oriented and equitable climate action at UNFCCC COP31 in Antalya: Union Environment Minister Bhupender Yadav*

**SSC • Banking • Railway • General**

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए तुर्किये के अंताल्या में 9 से 20 नवंबर 2026 तक होने वाले यूएनएफसीसीसी के सीओपी31 के लिए भारत की प्राथमिकताएं बताईं, और सीबीडी सीओपी17 तथा यूएनसीसीडी सीओपी17 में भारत की भागीदारी के प्रमुख परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत सीओपी31 में समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ जाएगा और क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप समाधानों को केंद्र में रखते हुए ग्लोबल साउथ के लिए व्यावहारिक समाधान लाएगा, तथा जी-77 और चीन, एलएमडीसी और बेसिक (BASIC) के साथ मिलकर काम करेगा। मंत्री के अनुसार जलवायु वित्त एक प्रमुख प्राथमिकता होगी और भारत सीओपी31 में जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम (क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम) शुरू करने का निर्णय चाहेगा; उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 9.1 के तहत वित्त उपलब्ध कराना विकसित देशों का दायित्व है, और यह वित्त पूर्वानुमेय, मुख्यतः सार्वजनिक और रियायती होना चाहिए तथा इससे कर्ज का बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत इस पर भी जोर देगा कि शमन (मिटिगेशन) और वैश्विक स्टॉकटेक पक्षकार-संचालित, सहायक (फैसिलिटेटिव) और गैर-दंडात्मक रहें, एनडीसी की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रकृति का सम्मान हो और ऊपर से तय किए गए नए लक्ष्य न थोपे जाएं। मंत्री ने कहा कि अनुकूलन भारत की प्राथमिकता बना रहेगा, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन) के संकेतक स्वैच्छिक हों और वित्त तक पहुंच की शर्त न बनें, तथा अनुकूलन वित्त बढ़ाया जाए; भारत पक्षकार-संचालित व्यवस्था के माध्यम से न्यायसंगत परिवर्तन कार्य कार्यक्रम (जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम) को जारी रखने का समर्थन करेगा; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकसित देशों का दायित्व है और लागत, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) तथा व्यापार से जुड़ी बाधाएं दूर की जानी चाहिए; और कार्बन बाज़ारों में भागीदारी स्वैच्छिक रहनी चाहिए। सीओपी31 में भारत की गतिविधियों में स्वीडन के साथ लीडआईटी 3.0 (LeadIT 3.0), तटीय लचीलेपन (कोस्टल रेजिलिएंस) पर उच्च-स्तरीय साइड इवेंट और आईबीसीए तथा वनों पर पैनल चर्चाएं शामिल होंगी, और मंत्री ने कहा कि भारत अंताल्या में रचनात्मक और सेतु-निर्माण (ब्रिज-बिल्डिंग) की भूमिका निभाएगा तथा ऐसा परिणाम चाहेगा जो प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़कर कार्यान्वयन और सहायता की ओर ले जाए। उलानबटार (मंगोलिया) में हुए यूएनसीसीडी सीओपी17 के बारे में उन्होंने बताया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समूह का अध्यक्ष चुने जाने के बाद भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि की बहाली की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और भारत के घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों पर अपनी पहली मार्गदर्शिका (Guide to Grasslands and Other Open Natural Ecosystems of India) जारी की; उनके अनुसार येरेवान (आर्मेनिया) में हुए सीबीडी सीओपी17 में भारत ने कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) के प्रभावी और न्यायसंगत कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332018

## 8 कोयला मंत्रालय के कोयला नियंत्रक संगठन ने बंद और परित्यक्त खदानों के लिए डिजिटल खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण 'सुविकल्प' विकसित किया

*Coal Ministry's Coal Controller Organisation develops SUVIKALP, a digital mine repurposing tool for closed and abandoned mines*

**SSC • Banking • General**

कोयला मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को बताया कि मंत्रालय के तहत कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) ने 'सुविकल्प- खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण' (SUVIKALP – Mine Repurposing Tool) विकसित किया है, जो कोयला और लिग्नाइट खदान के लिए खनन योजना दिशानिर्देश, 2025 के अनुरूप एक डिजिटल निर्णय-समर्थन मंच है और बंद तथा परित्यक्त खदानों को उत्पादक संपत्तियों में बदलने में मदद के लिए बनाया गया है। सुविकल्प का उद्देश्य खनन के बाद भूमि-उपयोग के उपयुक्त अवसरों की पहचान के लिए एक वैज्ञानिक, पारदर्शी और मानकीकृत ढांचा स्थापित करना है। यह एक एकीकृत डिजिटल मंच पर भू-खनन विशेषताओं, पर्यावरणीय स्थितियों, इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, संसाधनों की कमी, वित्तीय पहलुओं और सामाजिक-आर्थिक कारकों को एक साथ लाता है; उपयोगकर्ता खदान-विशिष्ट जानकारी दर्ज करके साइट प्रोफाइल बनाते हैं, और संभावित पुनर्प्रयोजन विकल्पों का मूल्यांकन और रैंकिंग टीओपीएसआईएस (TOPSIS - आदर्श समाधान की समानता द्वारा अनुक्रम प्राथमिकता हेतु तकनीक) पर आधारित बहु-मानदंड निर्णय (एमसीडीएम) पद्धति से की जाती है। मूल्यांकन प्रक्रिया कारक चयन, संभावित विकल्पों के निर्माण, सामुदायिक प्राथमिकताओं के एकीकरण, उपयुक्तता मूल्यांकन और अंतिम रैंकिंग के क्रम में चलती है। सुविकल्प परियोजना मूल्यांकन में स्थानीय प्राथमिकताओं को शामिल करने के लिए 'रिक्लेम' (RECLAIM) – सामुदायिक जुड़ाव और विकास ढांचे को एकीकृत करता है, और इसका 'प्रिज्म' (PRISM – पोस्ट-माइनिंग रीपर्पोजिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजिक मॉडल) मंच को कार्यान्वयन के रास्तों तक ले जाता है, जिसे परियोजना अवधारणा नोट, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय केस स्टडी, नमूना निविदा दस्तावेज, कार्यान्वयन एजेंसियों के विवरण और सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े संसाधनों वाले एक एकीकृत ज्ञान भंडार का समर्थन प्राप्त है। मंत्रालय के अनुसार अगला चरण बंद और परित्यक्त कोयला और लिग्नाइट खदानों में सुविकल्प को व्यापक रूप से अपनाने, सिफारिशों को साइट-विशिष्ट व्यवहार्यता अध्ययनों, अवधारणा नोट और डीपीआर में बदलने, संस्थागत समन्वय, निवेश जुटाने, ज्ञान और क्षमता निर्माण तथा निगरानी और मूल्यांकन पर केंद्रित होगा; दीर्घकालिक लक्ष्य सुविकल्प को एक मापनीय (स्केलेबल) राष्ट्रीय ज्ञान और निर्णय-समर्थन इकोसिस्टम के रूप में विकसित करना है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331966

## 9 नीति आयोग ने 'इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड' का शुभारंभ किया: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य पर एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म

*NITI Aayog launches the 'India S&T Scoreboard', an interactive platform on the science and technology landscape of States and UTs*

**SSC • Railway • Science • General**

नीति आयोग ने 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के केजी मार्ग स्थित सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (CSOI) में 'इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड' का शुभारंभ किया; इसका अनावरण नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने किया। नीति आयोग की एक प्रमुख पहल के रूप में विकसित यह स्कोरबोर्ड एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य का एक एकीकृत दृश्य प्रदान करता है, और इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और बेंचमार्किंग को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों, डीप-टेक स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स सहित एसएंडटी इकोसिस्टम के डेटा के साथ-साथ शोध प्रकाशनों और पेटेंट जैसे एसएंडटी आउटपुट के डेटा को एक साथ लाता है। आउटपुट की मात्रा से आगे बढ़कर, यह प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों और तीन क्षेत्रों - अकादमिक, सरकारी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं और उद्योग - में शोध की गुणवत्ता, प्रभाव, सहयोग और ओपन एक्सेस के संकेतक प्रस्तुत करता है; यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आपस में तुलना की सुविधा भी देता है और राज्य नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं (बेस्ट प्रैक्टिसेज) सहित विस्तृत राज्य प्रोफाइल प्रदान करता है। नीति आयोग के सदस्य (एसएंडटी) प्रो. अभय करंदीकर ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार से संबंधित डेटा अब तक कई स्रोतों में बिखरा हुआ था, जिससे राज्यों के लिए अपनी वास्तविक स्थिति का आकलन करना कठिन हो जाता था, और यह स्कोरबोर्ड एक ही इंटरैक्टिव डैशबोर्ड पर इकोसिस्टम, प्रकाशन और पेटेंट डेटा को वर्षों के रुझानों के साथ लाकर इस कमी को दूर करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. उमेश वी. वाघमारे ने कहा कि यह स्कोरबोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय साक्ष्य आधार में एक मूल्यवान राज्य-स्तरीय परिदृश्य जोड़ता है। उपाध्यक्ष ने कहा कि सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के सिद्धांत से प्रेरित यह स्कोरबोर्ड राज्यों को अपनी शक्तियों और कमियों की पहचान करने, एक-दूसरे से सीखने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बेहतर कार्यक्रम और नीतियां तैयार करने में मदद करेगा, और उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस मंच का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया; यह मंच www.sts.niti.gov.in पर उपलब्ध है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332136

## 10 नीति आयोग और टेक्समिन (TEXMiN) ने भारत के महत्वपूर्ण खनिज इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संयुक्त आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए

*NITI Aayog and TEXMiN sign a Joint Statement of Intent to strengthen India's critical minerals ecosystem*

**SSC • Banking • General**

नीति आयोग ने 3 नवंबर 2026 को बताया कि नीति आयोग और आईआईटी (आईएसएम) धनबाद स्थित टेक्समिन (TEXMiN - टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क), जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की एक पहल है, ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त आशय वक्तव्य (जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट - एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना तथा भारत में मजबूत और टिकाऊ महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं के विकास में सहायता करना है, और यह नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम) के उद्देश्यों के अनुरूप है। एसओआई में चार प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना की गई है: सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास; तकनीकी और रणनीतिक अध्ययन; नीतिगत और संस्थागत सहायता; तथा क्षमता निर्माण और ज्ञान का आदान-प्रदान। इस पर हस्ताक्षर नीति आयोग के सदस्य प्रो. गोवर्धन दास की आईआईटी (आईएसएम) धनबाद यात्रा के दौरान हुए, जहाँ उन्होंने 31 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों (रेयर अर्थ्स) पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (सीएमआरई 2026) का उद्घाटन किया; यह संगोष्ठी इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट्स के 45वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित की गई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रो. दास ने महत्वपूर्ण खनिजों को राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भारत के 'विकसित भारत 2047' विजन के रणनीतिक सक्षमकारी (स्ट्रैटेजिक एनेबलर्स) बताया, खनन-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर अन्वेषण, प्रसंस्करण, शोधन, उन्नत सामग्री और पुनर्चक्रण को समाहित करने वाली एकीकृत मूल्य श्रृंखला की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया, और कोयले की फ्लाई ऐश, रेड मड, खदानों के अवशेष (माइन टेलिंग्स) और इलेक्ट्रॉनिक कचरे जैसे द्वितीयक संसाधनों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति की संभावना पर प्रकाश डाला।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332152

## 11 एपीईडीए ने अरुणाचल प्रदेश के ज़िरो से 1.5 मीट्रिक टन कीवी का दुबई के लिए प्रायोगिक निर्यात कराया

*APEDA facilitates trial export of 1.5 MT of Arunachal Pradesh kiwi from Ziro to Dubai*

**SSC • Banking • Railway • General**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को बताया कि उसके अंतर्गत आने वाले कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने अरुणाचल प्रदेश के ज़िरो से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई तक 1.5 मीट्रिक टन (एमटी) कीवी के प्रायोगिक निर्यात में सहायता की है। यह खेप दुबई पहुँच गई और इसे अल कुसैस के लुलु हाइपरमार्केट में प्रदर्शित किया गया; मंत्रालय के अनुसार यह पहल अब फ्लैग-ऑफ के चरण से आगे बढ़कर खुदरा स्तर पर बाजार के मूल्यांकन के चरण में पहुँच गई है, जिसमें ग्राहकों द्वारा कीवी को चखने और उनकी प्रतिक्रिया से फल की स्वीकार्यता और संभावित मांग का आकलन होगा और भविष्य के व्यावसायिक निर्यात के लिए ग्राहकों की पसंद, गुणवत्ता की उम्मीदों, पैकेजिंग और प्रस्तुति की जरूरतों की जानकारी मिलेगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) के अंतर्गत शुरू की गई यह पहल 'कीवी: अरुणाचल प्रदेश की विशेषता' (Kiwi: USP of Arunachal Pradesh) नामक ब्रांडिंग पहल के तहत अरुणाचल प्रदेश के कीवी सेक्टर को बढ़ावा देने और मजबूत करने का प्रयास करती है, और इसे अरुणाचल प्रदेश सरकार के व्यापार और वाणिज्य विभाग तथा बागवानी विभाग के सहयोग से लागू किया गया। रिलीज़ के अनुसार राज्य की अधिक ऊँचाई वाली परिस्थितियाँ और प्राकृतिक वातावरण विशिष्ट गुणवत्ता और स्वाद वाली कीवी की खेती में सहायक हैं; यहाँ मुख्य रूप से हेवर्ड, मोंटी, एलिसन और ब्रूनो किस्में उगाई जाती हैं, जिनमें से हेवर्ड किस्म की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग है। फ्लैग-ऑफ समारोह में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि एवं संबद्ध विभागों के मंत्री श्री गेब्रियल डी. वांगसू उपस्थित रहे, और कीवी उत्पादक सहकारी समिति तथा फेयर एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने एपीईडीए के अधिकारियों और खेप के साथ गए कीवी किसानों के साथ इसमें भाग लिया।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332077

## 12 सर्बानंद सोनोवाल ने 2047 तक भारत की माल ढुलाई में तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग नौवहन की हिस्सेदारी को 6% से दोगुना कर 12% करने की योजना प्रस्तुत की

*Sarbananda Sonowal outlines plan to double the share of coastal and inland waterway shipping in India's freight movement from 6% to 12% by 2047*

**SSC • Banking • Railway • General**

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को बताया कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा के पुरी में कंसल्टेटिव कमेटी (परामर्शदात्री समिति) की बैठक में कहा कि सरकार तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना और क्रूज भारत मिशन के माध्यम से 2047 तक भारत की माल ढुलाई में तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग नौवहन की हिस्सेदारी को 6% से दोगुना कर 12% करने और 2029 तक दस लाख समुद्री क्रूज यात्रियों को आकर्षित करने के लिए काम कर रही है; ये लक्ष्य हैं, उपलब्धियां नहीं। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) ओडिशा सरकार की साझेदारी में पुरी इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल विकसित करेगी, जिसकी लागत लगभग 1,500 करोड़ रुपये होने की संभावना है। सोनोवाल ने बताया कि भारतीय बंदरगाहों पर तटीय कार्गो पिछले 12 वर्षों में 74 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 177 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, जो लगभग 140% की वृद्धि है; भारत की तटरेखा 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। 2026-27 के बजट में घोषित तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना कार्गो मालिकों, तटीय पोत ऑपरेटरों और मल्टीमॉडल परिवहन ऑपरेटरों को प्रोत्साहन देगी। सोनोवाल के अनुसार क्रूज क्षेत्र में 2025-26 के वित्तीय वर्ष में भारत में 462,661 महासागरीय क्रूज यात्री और 212 पोत कॉल दर्ज किए गए, जो 2013-14 के बाद से यात्री यातायात में 5.5 गुना और पोत कॉल में 2.1 गुना वृद्धि है; सितंबर 2024 में शुरू किए गए क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य मार्च 2029 तक दस लाख समुद्री क्रूज यात्री और 400,000 नौकरियां है। सोनोवाल ने कहा कि 143 नदी क्रूज टर्मिनल और लैंडिंग पॉइंट चालू हैं, और दोनों पहलों से कुल मिलाकर 560,000 से अधिक नौकरियों के सृजन और 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होने की उम्मीद है। उन्होंने ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के विकास पर भी प्रकाश डाला, जिसकी अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है और जिसका उद्देश्य तालचेर और कलिंगनगर सहित राज्य के औद्योगिक और खनन केंद्रों को पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ना है। बैठक में राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और संसद के आठ सदस्य उपस्थित रहे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332260

## 13 भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल की 9वीं उच्च स्तरीय बैठक श्रीलंका के मिरिसा में हुई

*Indian Coast Guard and Sri Lanka Coast Guard hold 9th High-Level Meeting at Mirissa, Sri Lanka*

**SSC • Railway • Defence • General**

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और श्रीलंका तटरक्षक बल (एसएलसीजी) के बीच 9वीं उच्च स्तरीय बैठक (एचएलएम) 3 नवंबर 2026 को श्रीलंका के मिरिसा में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने और श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रीलंका तटरक्षक बल के महानिदेशक रियर एडमिरल रुवान रूपासेना ने किया। बैठक में समुद्री प्रदूषण से निपटने (मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स), समुद्री खोज एवं बचाव (एसएआर) तथा समुद्री कानून प्रवर्तन सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया, और दोनों तटरक्षक बलों के बीच परिचालन सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए क्षमता विकास तथा तकनीकी सहायता संबंधी पहलों को बढ़ाने के उपायों पर भी विचार किया गया। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने तथा साझा समुद्री क्षेत्र में समुद्री संरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रालय के अनुसार बैठक में दोनों तटरक्षक बलों ने द्विपक्षीय जुड़ाव को और मजबूत करने, समुद्री आपात स्थितियों से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा देने तथा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्री पर्यावरण के लिए क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के अपने साझा संकल्प को रेखांकित किया।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332184

## आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

**प्र.1** बंद और परित्यक्त खदानों के पुनर्प्रयोजन के लिए डिजिटल निर्णय-समर्थन मंच 'सुविकल्प' कोयला मंत्रालय के तहत किस संगठन ने विकसित किया है?

(A) केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान
(B) कोयला नियंत्रक संगठन
(C) एनएलसी इंडिया लिमिटेड
(D) कोल इंडिया लिमिटेड

**प्र.2** नीति आयोग ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए टेक्समिन (TEXMiN) के साथ एक संयुक्त आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की यह पहल किस संस्थान में स्थित है (जानकारी 3 नवंबर 2026 को दी गई)?

(A) आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी
(B) आईआईटी (आईएसएम) धनबाद
(C) आईआईटी खड़गपुर
(D) एनआईटी राउरकेला

**प्र.3** रक्षा मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को बताया कि भारतीय नौसेना ने मछली पकड़ने वाले जहाज 'अजिनी' को सशस्त्र समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया और चालक दल के सभी 20 सदस्यों को बचा लिया। इस जहाज का अपहरण किस देश के तट के पास हुआ था?

(A) ओमान
(B) यमन
(C) सोमालिया
(D) इरिट्रिया

**प्र.4** 'कीवी: अरुणाचल प्रदेश की विशेषता' (Kiwi: USP of Arunachal Pradesh) ब्रांडिंग पहल के तहत एपीईडीए ने अरुणाचल प्रदेश के ज़िरो से 1.5 मीट्रिक टन कीवी का प्रायोगिक निर्यात किस शहर के लिए कराया, जहाँ इसे एक हाइपरमार्केट में प्रदर्शित किया गया (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 3 नवंबर 2026)?

(A) दुबई
(B) रियाद
(C) दोहा
(D) मस्कट

**प्र.5** कौशल उत्कृष्टता केंद्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के पैनलबद्धीकरण संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत 2 नवंबर 2026 को एमएसडीई द्वारा मान्यता प्राप्त 19 संस्थानों को किस मार्ग से पैनलबद्ध किया गया?

(A) नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया
(B) राज्य सरकारों द्वारा नामांकन
(C) सिंगल विंडो
(D) ग्रीन चैनल

**उत्तर: 1-(B) 2-(B) 3-(C) 4-(A) 5-(D)**

**रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें**

**रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/**

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।